भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *176
उत्तर देने की तारीख: 28.07.2022

'उस्ताद' योजना

***176. श्री राजबहादुर सिंह:**
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विशेष रूप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में शुरू की गई विकास के लिए पारंपरिक कलाओं शिल्पों में कौशलों का उन्नयन और प्रशिक्षण (उस्ताद) योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या का जिला, राज्य और कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्यों में विशेष रूप से 'उस्ताद' योजना के कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत लाभान्वित हुई लड़कियों/महिलाओं का ब्यौरा क्या है और;

(घ) 'उस्ताद' योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

"उस्ताद योजना" के संबंध में श्री राजबहादुर सिंह और श्री बृजभूषण शरण सिंह द्वारा पूछे गए एवं दिनांक 28.07.2022 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *176 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद) योजना 14 मई, 2015 को अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं/शिल्पों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कुशल शिल्पकारों/कारीगरों का क्षमता निर्माण और उनके पारंपरिक कौशलों को अद्यतन करना, अल्पसंख्यकों की अभिज्ञात पारंपरिक कलाओं/शिल्पों का दस्तावेजीकरण, पारंपरिक कौशल के लिए मानक निर्धारित करना, कुशल कारीगरों के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न अभिज्ञात पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में प्रशिक्षण देना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार संबंधों का विकास करना है। योजना को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

योजना के तहत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID) को 50 कलस्टर आवंटित किए गए थे जिसका उद्देश्य डिजाइन हस्तक्षेप, उत्पाद रेंज विकास, पैकेजिंग, प्रदर्शनियों और ब्रांड निर्माण इत्यादि है। 50 कलस्टरों में से एनआईएफटी और एनआईडी द्वारा पहले ही 35 कलस्टरों में कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है जबकि शेष कलस्टरों में प्रशिक्षण जारी है।

हुनर हाट को उस्ताद योजना के एक घटक के रूप में 2016-17 से लागू किया जा रहा है जो देश भर के कारीगरों/शिल्पकारों और पाक विशेषज्ञों को अपने हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनका विपणन करने का अवसर प्रदान करती है। हुनर हाट पारंपरिक कला, शिल्प और स्वदेशी उत्पादों के प्रचार और संरक्षण में मदद कर रहा है, जो स्वदेशी से स्वावलंबन' और वोकल फॉर लोकल' की प्रतिज्ञा में एक प्रभावी भूमिका निभा रहा है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों में योगदान हो रहा है और कारीगरों, शिल्पकारों और संबद्ध व्यक्तियों के लिए रोजगार और रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं और उनके बाजार संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। अब तक मंत्रालय द्वारा देश भर में आयोजित 41 हुनर हाटों से 8 लाख से अधिक कारीगर, शिल्पकार और उनसे जुड़े लोग लाभान्वित हो चुके हैं।

उस्ताद योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना के तहत कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार निधियां और/या लक्ष्य आवंटित/जारी नहीं किए जाते हैं। उस्ताद योजना के तहत अब तक 91 पीआईए के माध्यम से कुल 23,130 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। संबंधित राज्यों के कुल 11,262 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है और वे इस योजना के तहत सीधे लाभान्वित हुए हैं। लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:-

राज्य	**लाभार्थी**
मध्य प्रदेश	2006
उत्तर प्रदेश	9166
गुजरात	90

(ख) संबंधित राज्यों में उस्ताद योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 60 पीआईए को पैनलबद्ध किया गया है: -

राज्य	**परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां**
मध्य प्रदेश	13
उत्तर प्रदेश	46
गुजरात	1
कुल	**60**

(ग) योजना के तहत अल्पसंख्यक लड़कियों/महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% सीटें निर्धारित की गई हैं। 23,130 लाभार्थियों में से कुल 19,257 लड़कियों/महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और इस तरह अब तक उस्ताद के तहत सीधे लाभान्वित हुई हैं।

(घ) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उस्ताद योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि नीचे दी गई है: (आंकड़े करोड़ रु. में)-

वर्ष	**आबंटित**		**उपयोग**
	बजट अनुमान	**संशोधित अनुमान**	
2022-23	47.00	-	10.06 (27.07.2022 तक)

******